[Shri S. M. Banerjee]

the resolution has got the right of reply. He cannot reply because he is in jail. But because of that he does not lose his right to reply. This should be kept pending till he comes back to the House. This is an extraordinary situation and I request you to give an extraordinary ruling.

MR. CHAIRMAN: There is no point of order. This is as good as the member remaining absent. Whatever may be the reasons, we will not go into that. If a member, who has the right to reply, remains absent, I proceed on the basis that he is absent. The resolution has been moved and it is in the custody of the House. It is for the House to accept it or reject it. The question is:

"This House strongly deprecates all the slanderous remarks made against Netaji Subhas Chandra Bose in the report of the 'one-man Commission of Inquiry into disappearance of Netaji Subhas Chandra Bose', particularly on pages 7, 16, 30, 31, 37, 124 and 125, by Justice G. D. Khosla, as its Chairman, and urges upon the Government to expunge these disparaging, distorted, factually incorrect and unwarranted observations, before the Report is made available for public circulation as they militate the patriotic sentiment of our countrymen and further, in consonance with our national feeling in this regard, this highest forum of the will of the Indian people once again, affirms nation's solemn homage to the greatest revolutionary pilgrim of our motherland, who played the historic role, like an epical hero, in the war of liberation of United India."

The motion was negatived.

सभापति महोदय : श्री विभूति मिश्र ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि विभूति मिश्र जी का प्रस्ताव बहुत इम्पार्टेन्ट है लेकिन श्री इन्द्रजीत गुप्त का प्रस्ताव भी बहुत इम्पार्टेन्ट है इसलिए आप एक मिनट उसके लिए भी छोड़ दीजिएगा, यही मैं आपसे कह रहा था ।

सभापति महोदय : कौन मूव करेंगा ?

श्री एस० एम० बनर्जी : श्री चन्द्रप्पन को उन्होंने अथराइज किया है ।

सभापति महोदय : अभी बहुत टाइम है ।

15.45 hrs.

RESOLUTION *RE: IMPLEMENTATION OF 20-POINT PROGRAMME*

श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी) : चेयरमैन साहब मैं अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत करना चाहता हूं जिसका मस्विदा इस प्रकार है :–

"This House while expressing its deep appreciation of the 20-Point programme initiated by Government, notes that its implementation at the State, district, block and village level has not been quite satisfactory so far and, therefore, recommends that necessary steps may be taken by Government immediately to remove all legal and administrative hurles in the implementation of the programme."

सभापति जी, मैं अपने प्रस्ताव के सम्बन्ध में सर्वप्रथम प्रधानमंत्री जी को धन्यावाद देना चाहता हूं कि एक बहुत अमूल्य 20 सूत्री कार्यक्रम उन्होंने देश के सामने रखा है । जिस परिस्थिति से देश गुजर रहा था उस में उन्होंने एक अमूल्य रत्न देश को दिया जिस का हम सभी को पालन करना चाहिये चाहे हम कहीं भी हो ।

प्रधान मंत्री ने अपने 20 सूत्री कार्यक्रम के सम्बन्ध में, आर्थिक मोर्चे पर क्रान्तिकारी कार्यक्रम में बयान देते हुए उन्होंने कहा कि

केवल एक ही जादू है जो गरीबी को दूर कर सकता है और वह है स्पष्ट दूर दृष्टि के साथ कड़ा परिश्रम, दृढ़ इच्छा और कठोरतम अनुशासन। जब तक यह चीजे नहीं होगी तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। इस सम्बन्ध में मुझे कहना है कि कहां तक इस में प्रगति हुई है इस का हमें कुछ पता नहीं चलता है। आज 6 महीने गुजर गये, सरकार को हमारे सामने एक श्वेत पत्र रखना चाहिये था, जो कि अभी उस ने नही रखा। मैं ने योजना मंत्री से भी, जो इस समय सदन में मौजूद हैं, प्रश्न किया था। उन्होने कोई खास इसके सम्बन्ध में हमें इत्तला नही दी। और इसके पहले मैंने सिंचाई और कृषि मंत्री जी से पूछा था सवाल जिस के जबाब में उन्होने कहा था कि:

"कुछ राज्यों में भूमि की अधिकतम सीमा संबधी कानून के कुछ उपबंधों को या तो समाप्त कर दिया गया है या न्यायालय में चुनौती दी गई है। इस के फलस्वरूप उन के क्रियान्वयन में कुछ अड़चनें आई हैं। अब तक अधिकांश भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानूनों को संविधान की नवी अनुसूची में रखा गया है। इन कानूनो को शीघ्र क्रियान्वित करने के लिए उचित उपायों की जाच की जा रही है। अब सवाल यह है कि इस सम्बन्ध में कुछ भी हम लोगों को सरकार की तरफ से जानकारी नहीं मिली। जो कुछ जानकारी मिली है वह थोडी सी प्रधान मंत्री के राष्ट्रपति जी को धन्यवाद प्रस्ताव पर दिये गये भाषण में मिली है। नहीं तो मंत्री जी ने मेरे सवाल का लिखित जवाब यह दिया है कि :

Question: Will the Minister of Planning be pleased to state the measures proposed to be taken by the Central Government to implement 20-Point Programme during next six months?

Answer: Imulementation of the 20-Point Economic Programme is given the highest priority and substantial progress has been achieved during the last six months. Efforts for the speedy implementation of the Programme will be continued.

अब इससे आप सोच सकते हैं कि हमारी सरकार कितनी इसके बारे में इच्छुक है कि 20 सूत्री कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जाए। योजना मंत्री जी ने ऐसा ही जबाब दिया और सिंचाई मत्री जी ने यह जबाब दिया कि इस में कानूनी अड़चनें हैं।

अब मैं यह जानना चाहता हूं कि जब हम लोग आपातकालीन स्थिति से गुजर रहे हैं, तो हम लोगों का हक है कि इसे कार्यान्वित कराएं और इस दौरान अगर इस को कार्यान्वित नही किया जाता है तो सारी आपातकालीन स्थिति के प्राण ही गायब हो जाते हैं। इसलिए इसी दरमियान हमें इस 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू कराना है। इस में लिखा है कि सरकारी खर्चे में कमी की जाएगी। अब इस के सम्बन्ध में हमारे पास आकडे नहीं है कि क्या कमी की जाएगी और क्या नही की जाएगी लेकिन इस के सम्बन्ध में जो कुछ हमें सूचना मिली है, वह प्रधान मत्री जी ने जो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर थैक्स के प्रस्ताव के सम्बन्ध मे, भाषण दिया था। उसी से थोडी बहुत सूचना मिली है। उस मे प्रधान मत्री जी ने साफ खुलासा किया है और यह कहा है कि :

"I should like to say a few words about economic achievements under the twenty-point programme in these last six months. Consumer prices for the agricultural labourer are now 8.3 per cent lower; 27 lakh tonnes of kharif cereals have been procured against 14 lakh tonnes last year; 53 lakhs bogus cards have been eliminated; public sector production in these six months is 31.5 per cent higher than last year. Industrial production gains are as follows: steel 15.9 per cent, power generation 12 per cent, coal 12 per cent, fertilizer 43 per cent, cement 11.8 per cent, crude oil 10 per cent, house sites 60 lakhs.

The programme for the removal of bonded labour is well known as

[श्री विभूति मिश्र]

also the establishment of rural banks. Ultimately they will have fifty banks, each one having 100 branches. Irrigation is being expanded and the Godavari accord is a welcome, new and significant step. Handlooms have been given a loan of nearly Rs. 5 crores. Urban property evaluation programmes and the confiscation of smugglers' properties are other things. There are programmes for workers' participation; workers' participation had already been adopted in about 75 per cent of the public undertakings and we hope to expedite it in the remaining months. In the apprenticeship scheme, 1.17 lakhs of seats have already been filled up and work is progressing.

यह सूचना प्रधान मंत्री ने दी है। अब मुझे आपसे आग्रह करना है कि सरकार ने हम लोगों को इस के बारे में नही बताया है कि कितनी प्रगति हुई है। वह चाहे तो व्हाइट पेपर जारी कर दे। हमारे योजना मंत्री जी बैठे हुए है और उन्होंने जो मेरे सवाल का जवाब दिया है, उस को मैंने आप को सुना दिया है। केवल प्रधान मंत्री जी ने कुछ रोशनी डाली है कि इस के बारे में क्या हो रहा है।

अब मुझे एक बात और कहनी है वह जमीन सीलिंग के बारे में है। लैंड की सीलिंग को अमल में लाने के लिए कानूनी अड़चनें आ गई है और हाई कोर्टस में मुकदमें है। जब हाई कोर्टस में मुकदमें हैं और इस सैशन में बहुत से काम हुए हैं, तो मै सरकार से दरखास्त करता हू कि इस सम्बन्ध में जो दिक्कते हैं, जो कानूनी दिक्कतें हैं, उन को सरकार दूर करे। जमीन की सीलिंग फिक्स हो जाए और मुकदमें चलें, तो अभी इस बारे में उस सीलिंग को कार्यान्वित कराने के लिए कोई कार्यवाही नही हुई है।

दूसरी बात यह है कि आज भी जनता, जिन के ऊपर सीलिंग लग रही है, कहती है कि शहर के लोगों के ऊपर सीलिंग क्यों नहीं लगती। इसके लिए हमारी ही पार्टी के एक मेम्बर श्री चक्रवर्ती ने ए. आई. सी. सी. में एक प्रस्ताव रखा था कि शहरी सम्पत्ति पर सीलिंग लगाए और क्यों सरकार इसके बारे में चुप्पी साधे बैठी है, यह मेरी समझ में नहीं आता है।

हम समाजवाद का नारा लगाते हैं। समाजवाद बहुत जरूरी है। लेकिन यह भी सरकार को देखना चाहिये कि तनख्वाहों मे कितना फर्क हो एक पाच का अनुपात उस में हो या एक दस का हो। इस चीज को भी आपको तय कर देना चाहिये ताकि लोगों को भरोसा हो कि कुछ काम इस दिशा मे हो रहा है। मै अनुरोध करता हू और प्रार्थना करता हू कि सरकार इस दिशा मे उचित कदम उठाए और काम करे।

प्रधान मंत्री ने यह भी कहा था कि सरकारी खर्चे मे कमी की जाएगी। इसका आकडा भी हमे उपलब्ध नही किया गया है कि कितनी कमी स्टेट गवर्नमेंट ने और कितनी सेंटल गवर्नमेंट ने की है। यह भी हम को बताया जाना चाहिये।

सेंटर तथा स्टेट्स लोगो को रिटायर कर रहे है। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि इसका कोई क्राइटीरिया नही रखा गया है। सुना जाता है कि बहुत से आदमी जो अच्छे थे उनको रिटायर कर दिया गया है और बुरे सर्विस में है। मैं समझता हू कि इसके लिए कोई इंडिपेंडेंट कोर्ट टाइप की चीज होनी चाहिए, बाडी होनी चाहिए जो सर्विस रिकार्डस देखकर लोगों को रिटायर करने की सिफारिश करे और बताए कि किस को रखना है और किस को नही रखना है। अगर आप पचास बरस पर लोगों को रिटायर करना चाहते हैं तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। लेकिन कोई उसूल होने चाहियें जिन की बिना पर इसको किया जाए। उसूलों की कमी इस सम्बन्ध में काफी दिखाई पड़ती है।

और उसूल हैं तो मैं समझता हू कि उनका ठीक से पालन नही हो रहा है।

बेकारी की समस्या भी गम्भीर रूप धारण किए हुए है और रोज बरोज यह बढती ही जा रही है। जितने हमारे साथी हैं सब पत्र इसके सम्बन्ध मे लिखते रहते है। लेकिन इसको हल करने की दिशा मे पग नही उठाए गए है। बेकारी हमारे सामने मुह बाए खडी है। मालूम होता है कि यह बेकारी की समस्या हम सब लोगो को खा जाएगी। एप्रेंटिशिप योजना है। लेकिन उस मे भी जो गरीब लोग है ग्रेजुएट आदि है वे लिए नही जाते है। ग्रेजुएट, इजीनियर डाक्टर आदि लाग बेकार फिर रहे है। यही इटैलीजेंशिया क्लास है। और इसका सवाल आप हल नही करेंगे इनकी रोजी रोटी की समस्या को आप हल नही करेंगे तो मामला बडा गोलमोल रहेगा, देश मे अशान्ति रहेगी। मैं चाहता हू कि इस आपातस्थिति मे जल्दी से जल्दी इनकी समस्या को भी हल करने की दिशा मे कदम उठाए जाये। लोगो को इस मामले मे राहत पहुचाई जानी चाहिए।

कृषि की जो चीजे है उनकी किमते गिर रही है। फर्टिलाइजर की कीमत नही गिरी है। स्कूल कालेजो मे जो फीस ली जाती है, वह कम नही हुई है। चडीगढ मे प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारी सहानुभूति किसानो के साथ है। मैं मानता हू कि आपकी सहानुभूति किसानो के साथ है। लेकिन आज गावों मे जा कर देखे कि किसानों की आमदनी क्या है, उन लोगों की जो चीजे खरीदनी पडती है उन पर उनका कितना खर्चा आता है, उनकी कीमत उनको क्या देनी पडती है और जो उनके द्वारा उत्पादित वस्तुए हैं उनकी कीमत उनको कितनी मिलती है। इन सब का हिसाब लगा कर आप देखें कि किसान कितनी मुश्किल मे है, उसकी हालत क्या है। मै चाहता हू कि आप की एक इटेग्रेटिड प्राइसिंग नीति हो। किसान को जिन चीजों की जरूरत हो उसकी कीमत और किसान जिन चीजो को पैदा करता है उन चीजो की कीमत दोनो का जोड होना चाहिए। ऐसा आपने किया तो किसान भी अच्छा रहेगा और फेक्ट्री लेबरर भी अच्छा रहेगा और दूसरे लोगो को भी शिकायत करने का मौका नही मिलेगा। इस सम्बन्ध मे भी सरकार को कोई कार्रवाई करनी चाहिए।

आपने इनकम टैक्स मे जो रिलीफ दिया है उसके सम्बन्ध मे मुझे कुछ नही कहना है।

जहा तक रोड ट्रान्सपोर्ट का सम्बन्ध है एक सूबे से दूसरे सूबे मे और दूसरे से तीसरे सूबे मे जाने के लिए ट्रकों आदि के लिए आप लाइसेंस जारी करेंगे यह आपने घोषणा की है। मेरा निवेदन है कि सरकार सब सूबो के साथ उस मामले मे न्याय बरते। ऐसा नही होना चाहिए कि जिस सूबे के लोग सेंट्रल सक्रेटेरिएट मे हो वे लाइसेंस अपने खास खास लोगो को दे दे और दूसरे लोग इन से वचित रह जाए। जो बीमार हो जाता है उसकी ज्यादा देखरेख की जाती है और जो मजबूत होता है उसकी कम की जाती है। आपने आपातकाल की घोषणा की है और बीस सूत्री कार्यक्रम लागू किया है। आप देखे कि कुछ स्टेट्स ऐसी है जो बहुत खुशहाल है और कुछ ऐसी है जो बहुत ज्यादा गरीब है। कम से कम आप दोनो को लगभग समान स्तर पर तो लाए। लेकिन यह हो नही रहा है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये। उसको देखना चाहिये कि जो स्टेट्स गरीब है वे गरीबी से ऊपर उठे और जो धनी हैं उनकी बराबरी मे वे आए। जो मरीज होता है जिस तरह से उसको अच्छा खाना दिया जाता है, अच्छी-अच्छी चीजें खाने को दी जाती हैं और तगडों को कम दिया जाता है, ऐसा ही कुछ यहां भी होना चाहिये और इसका भी कुछ इतजाम आपको करना चाहिये।

[श्री विभूति मिश्र]

वर्कर्स लोगों के मैनेजमैंट में पार्टिसिपेशन के बारे में कुछ कार्य हुआ है लेकिन अभी कुछ और होना चाहिये ।

जहां तक एक इन्वैस्टमैंट का सम्बन्ध है, यह स्वाभाविक है कि पिछड़े हुए इलाकों में कोई भी इन्वैस्टमैंट नहीं करना चाहता । मैं नार्थ बिहार का रहने वाला हूं जो नेपाल की सीमा के साथ लगा हुआ है । वहां पर कोई बड़ी लाइन नहीं जाती है, कोई हवाई जहाज नहीं जाता है । तो कोई भी सेठ वहां पैसा क्यों लगायेगा, सैंट्रल गवर्नमट भी नहीं लगायेगी । इसलिये मैं चाहता हूं कि इस तरह के इन्वैस्टमैंट में बैकवर्ड एरियाज, चाहे वह देश में कहीं भी हों, को तरजीह देनी चाहिये ।

यह सरकार ने अच्छा किया है कि वह समगलरों की सम्पत्ति जप्त कर रही है । इसके लिये मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूं ।

जहां तक सामान की क्वालिटी का सम्बन्ध है, मैं बताना चाहता हूं कि गांव में जो कपड़ा बिकने के लिये जाता है, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिये और वह सस्ता होना चाहिये ताकि गरीब लोग वह कपड़ा खरीद सकें । मैंने देखा है कि कपड़े के दामों में कोई खास कमी नहीं हुई है ।

एग्रीकलचर में 5 रुपये रोज मजदूरी कर दी गई है लेकिन मैंने देखा है कि गांव में 8 घंटे काम करने के लिये गांव का लेबरर तैयार नहीं होता है । दूसरे जब मजदूरी निश्चित कर दी गई है, लेकिन मजदूर को बहुत सी जगह घूमने फिरने पर भी खा को नहीं मिलता है । इसलिये सरका को चाहिये कि इतना रुपया या इतना ध या इतना गेहूं दिया जायेगा ताकि उन लो को कठिनाई न हो ।

सरकार ने कर्ज माफ कर के एक अच्छा कदम उठाया है । हमारे यहां गांधी जी द्वारा काम करने के फलस्वरूप चम्पारन एगरेरियन एक्ट बना और बाउन्डेड लेबर खत्म हो गई । लेकिन हिन्दुस्तान में 25 साल की आजादी के बाद भी बाउन्डेड लेबर खत्म नहीं हुई है, यह खेद की बात है । सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये ।

जिन गरीबों का घर नहीं है, उनको जमीन दी जा रही है लेकिन बहुत जगह इनको अभीजमीन नहीं दी गई है । इसकी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमैंट्स की है । जब तक इस तरफ़ पूरी शक्ति से काम नहीं करेंगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है ।

सब नीतियां तथा आदेश यहां से दिये जाते हैं, मगर उनका इम्पलीमैंटेशन किस के हाथ में है । आखिर मिनिस्टर, चाहे वह सैंटर का हो या स्टेट का, हमेशा डंडा लेकर इम्पलीमैंटेशन नहीं करा सकता है । आखिर बात ब्यूरोक्रेसी पर आती है । उसमें नाना प्रकार के लोग होते हैं और वे अपने मन-मिजाज के अनुसार काम करते हैं । हमारे सोशलिस्ट भाई भी समझते हैं कि ह्यूमन वीकनेस सब जगह होती है । रूस और चीन में भी इस तरह की गड़बड़ है । हमें देखना होगा कि ह्यूमन वीकनेस को पार कर के हम कैसे आगे बढें ताकि हमारे 20 सूत्री प्रोग्राम का इम्पलीमैंटेशन हो । प्रधान मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि उनको इस बात का ज्ञान है कि क्या-क्या कठिनाई हैं । मैं सरकार से अपील करूंगा कि सरकार आपात-कालीन स्थिति में इस प्रोग्राम को कार्यान्वित करने के लिये मजबूत कदम उठाये ।

मैं चाहता था कि 20 सूत्री कार्यक्रम सम्बन्धी इस चर्चा का जवाब प्रधान मंत्री दें, क्योंकि यह कार्यक्रम उन्हीं की देन है । प्लानिंग मिनिस्टर या सैंट्रल गवर्नमैंट या स्टेट गवर्नमैंट के एम्पलाइज पर कोई कंट्रोल नहीं है । हमारे देश में जो कंट्रोल प्रधान मंत्री का है वह किसी और का

नहीं हो सकता है । इसलिये मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री इस बहस का जवाब दें । हम उनका साथ देने के लिये तैयार हैं । मैं 75 साल 6 महीने का हो गया हूं । इस उम्र में भी मैं चाहता हूं कि उन्होंने इस देश में जो क्रांतिकारी कदम उठाये हैं, मैं अपने मरने के दिन तक उसके साथ रहूं । लेकिन देश का कुछ हो तो । इसलिये मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री इस बहस का जवाब दें और बतायें कि वह 20 सूत्री कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये क्या-क्या कदम उठाने जा रही हैं ? इसके लिये कौन-कौन से कानून बनाये जायेंगे और संविधान में क्या परिवर्तन किये जायेंगे ?

इस सम्बन्ध में एक पुस्तक "संघर्ष में जूट जायें" निकाली गई है । राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के समय सब सदस्यों ने कहा कि वे इस 20 सूत्री कार्यक्रम का समर्थन करते हैं । किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया । लेकिन मैं 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में यह स्पैसिफ़िक रैज्योलूशन लाया हूं, ताकि माननीय सदस्य अपने सुझाव दे सकें और सरकार बता सके कि वे क्या करने जा रही हैं । बहुत से कायदे कानून बनते जा रहे हैं और वह बनने भी चाहियें, लेकिन मैं चाहता हूं कि सरकार इस दिशा में मज़बूती से कदम उठाये ।

कहा जाता है कि एम०पी० और एम०एल०ए० इस काम में सहयोग दें । हम लोग क्या सहयोग दें । जब हमारी कोई रैस्पोंसेबिलिटी हो, तो उसको पूरा करने के लिये हमारा कोई राइट भी होना चाहिये । रैस्पोंसेबिलिटी के बारे में कहा जाता है कि आप इसमें मदद दें, लेकिन हमारे राइट्स क्या हैं? हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, बी०डी०ओ०, एस०डी०ओ०, रैवेन्यु डिपार्टमैंट के कर्मचारियों और विलेज लैवल पर काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों से भी क्या कह सकते हैं ? रैस्पोंसेबिलिटी तो हमारी तब है, लेकिन हमारे राइट क्या हैं ? हमारी रैस्पोंसेबिलिटी तो यही है कि हम प्रस्ताव लायें, बैलट में नाम निकला, वह हमने मूव किया और सब सदस्यों ने बहस में भाग लिया । इतना तो हमारा अधिकार है, लेकिन किसी काम को इम्पलीमैंट कराने के लिये हमारा क्या अधिकार है ?

सरकार का आदेश है कि दुकानदारों को चीजों की कीमतों का बोर्ड लगाना चाहिये । लेकिन बहुत कम दुकानदार ऐसा बोर्ड लगाते हैं । गांव में मिट्टी के तेल के दाम बहुत ज्यादा हैं । इस स्थिति में गरीब क्या करेगा ?

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि सरकार सदन को बताये कि वह इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये कौन-कौन से मजबूत कदम उठाने जा रही है ?

MR. CHAIRMAN: Resolution moved:

"This House while expressing its deep appreciation of the 20-Point Programme initiated by Government, notes that its implementation at the state, district, block and village level has not been quite satisfactory so far and therefore, recommends that necessary steps may be taken by Government immediately to remove all legal and administrative hurdles in the implementation of the programme."

MR. CHAIRMAN: There are some amendments to this Resolution tabled by Shri Erasmo de' Sequeira and Shri M. C. Daga: If they want to move them, they may do so.

SHRI ERASMO DE SEQUEIRA (Marmagoan): I beg to move a:

That in the resolution,—

for "while expressing its deep appreciation"

Substitute—

"taking cognisance" (1)

SHRI ERASMO DE SEQUEIRA: That in the resolution,—

omit "quite" (2)

SHRI M. C. DAGA (Pali): I beg to move :

That in the resolution,—

add at the end—

"by giving necessary powers to Members of Parliament, Legislators and Members of Progressive Organisations and eliciting their active support." (3).

SHRI ERASMO DE SEQUEIRA: I want to speak on them.

SHRI M. C. DAGA: I also want to speak on it.

MR. CHAIRMAN: I do not wish you to finish with this 20-point programme today. It will go on.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna): The next resolution must be moved.

MR. CHAIRMAN. It is not concluding today.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: That will lapse. If that will not lapse, we have no objection.

MR. CHAIRMAN: It is not concluding today. It will continue next time.

SHRI ERASMO DE SEQUEIRA: The time on this resolution should not be restricted.

MR. CHAIRMAN: That is the predicament. We shall see at about one minute to 6.00, what is the position. If most of the members have spoken, then I will allow you to speak for one minute so that you can continue next time.

SHRI C. K. CHADRAPPAN: (Tellicherry): Mr. Chairman, Sir, we are very thankful to our hon. friend, Shri Bibhuti Mishra, for bringing forward this Resolution so that this House gets an opportunity to review the implementation of the 20-Point Economic Programme.

As far as we are concerned, we have made it very clear from the very beginning that we support the 20-point Economic Programme. We also consider that the 20-point Economic Programme is a very important instrument by which, if successfully implemented, it would possible to liquidate the reactionary forces which had built up a fascist offensive in our country. It is in that context that we supported the 20-point Economic Programme.

We also understand that this is a part of the package deal. This is a part of the declaration of the state of Emergency in our country. It was followed by the banning of RSS, Anand Marg and various groups of Naxalite elements. So, as a part of the great responsibility, the democratic forces of this country have undertaken on themselves the task of fighting and defeating the reactionary offensive. We understand that the 20-point Economic Programme has a great role to play if it is properly implemented.

When we come to the implementation of the Programme, I fully agree with the concern expressed by the mover of the Resolution that there are many lapses. I would like to point out some of the important aspects of the 20-point Economic programme and, in regard to those, how the Government has failed or how the Government could not come to the expectations of the people in this country who want this Programme to be properly implemented.

This Economic Programme, basically speaking, is meant for improving the life of the common man in this country. When we keep that in mind, all the steps that we take should be in tune with the spirit of the 20-point Economic Programme. That is why, in the Programme, we can see that there is a great emphasis put against

in our society. If successfully implemented, at the end of implementation, we will find that to a great extent this country will wipe out the blot of feudalism from the face of our socio-economic base. It has a point against monopoly also. We feel that it should have gone far more than to the extent it has gone. For example it should have assured the distribution of essential commodities at a fair price to the people. It is proclaimed that it is one of the aims of the Government. But to assure the distribution of essential commodities at a fair price, certain measures are necessarily to be taken. The first and foremost measure is that at the source of production, the essential commodities should have been brought under the control of the Government. If essential commodities like drugs, edible oil, clothes and food are to be made available to the people, then the twenty-point programme should add certain things to it. So, while implementing the twenty-point economic programme, the Government should take certain additional measures such as either nationalising or bringing under control those firms which are producing the essential commodities.

Then, Sir, from the first day of this Session we have seen what was the reaction of the Government in regard to the implementation of the Hathi Committee's report. The Government was vacillating; the Government was appealing to monopolists that they should have a social sense. Well, so long as their motive is profit and so long as the multi-nationals who are sucking the blood of the country have no sympathy for the people, mere appealing and mere wishes will no produce any results. If you really want results, more action is necessary in that regard.

In regard to the distribution of drugs to the people, till today, six months after the declaration of emergency and the proclamation of the twenty-point economic programme, I don't think Government could make any fundamental advance towards givig the people these essential materials.

Now, coming to food, this year it has been said that the God of nature was so kind to our country and there was a bumper production or bumper harvest, as it is called. But, while we have a bumper harvest. I appreciate that the Government tried to procure some part of this production, but the fact remains that the Government is even today spending 700 crores for the import of rice and import of wheat. Why could we not procure more and *why, at this time, cannot we successfully introduce* State take-over of the whole-sale trade in the food articles wheat and rice? Government had taken this policy decision in 1974: when the country was facing a serious crisis, when the agricultural production and especially food production was bad and when inflation was running riot, then Government adopted it. Now it is fair weather. If today, Government had adopted that policy, it could have produced good results. But the Government is not even thinking about it: and to ensure food to the people, Goverment is again depending heavily upon imports. That is not the policy by which you can implement the twenty-point economic programme with the spirit in which it was announced.

Now, coming to another aspect of the matter, the twenty-point economic programme says that house sites will be given to poor people—a very good thing. It was something like the fulfilment of a dream which the people were cherishing in their minds for several centuries: the people welcomed it. It is good that the Minister who is going to reply to this debate is from Delhi—at least he knows Delhi, though he is not from Delhi. Here, in Delhi, I have taken the trouble of going to a place in Jamuna Paar which is called Kalyanpuri and Kichripur, where there is to be this new "rehabilitation programme" as was described by the

[Shri C. K. Chandrappan]

Prime Minister and the Minister from Delhi, Mr. Bhagat. When I came there, I remembered Md. Bin Tughlak. A gentleman who lived several centuries ago in Delhi who had exercised such a thing in this part of the country. He was an emperor; he was a king. Today, what is being done in the name of rehabilitation is nothing better than that. I have seen the poor people from Race Course being taken to Jamuna Paar, far away from where they were living. And what is the site they have been given there? I have seen only white marks, white lines covering a few yards. What is more interesting is this. There are boards which say, "This is the site for park; this is the site for marketing centre, this is the site for playground, this is the site for recreation". But nothing is there, absolutely nothing is there. There are only boards and chalk-lines. People have been thrown to the mercies of nature. The other day when we were discussing the DDA Bill. I spoke about this. The Minister gave an answer. I do not know with what cheek he could say that. I am sure he cannot go outside and say that to the people. He said. 'It is rehabilitation'. It is not rehabilitation. It is a cruel joke being played on the poor people covering yourselves under Emergency and blinding the people, showing with grandeur the 20-Point Economic Programme. It is nothing more than that. If you have any sympathy for the poor people, this is not the way how it should be done. I have certain suggestions to make. First you build the shopping centre, help the people to rehabilitate themselves, give them financial assistance to build their small houses, make the recreation ground and not keep only the board, make the school, and then, after doing all these, send the people. But, here, you are putting the cart before the horse; you are sending the people first. And those people are dying there. If you go there, you will see children dying. There is no blanket for them in this biting cold; they have been mercilessly thrown in Jamuna Paar, which is almost on the water level, a very unhygienic and damp place. Nobody could have done this in the name of implementing the 20-Point Economic Programme! But this is how it is being done. Why is it happening? It is because this is done in a highly bureacratic and authoritarian manner....

MR. CHAIRMAN: Under which point of the 20-point Economic Programme does this come? You said, the people were being thrown.

SHRI C. K. CHANDRAPPAN: Yes, the poor people have been thrown there in the chalk-marked places....

MR. CHAIRMAN: Do you mean 'house sites'?

SHRI C. K. CHANDRAPPAN: Yes They have been sent there from their houses. They have been thrown in places where everything is marked and nothing is built.....

SHRI S. R. DAMANI (Sholapur): They have not been removed from their houses, but from the slums. (*Interruptions*).

SHRI C. K. CHANDRAPPAN I have gone there and I have seen how people are living. I have been to Mazdoor Basti. I can take you there and show you how people are living there I do not say that they should live for ever in the slum conditions. But I know how people are to be rehabilitated. We have experiences, the world over, how people are to be rehabilitated. Let them learn a lesson from those experiences. In this country itself there are examples. That is one thing.

Secondly, as I was saying, this is because of the bureaucratic way in which it is being implemented. In the 20-point Economic Programme, there is a presumption that the people who want to implement this programme will be invited to provide cooperation. But Government is against it at least in Delhi. There is no popular committee. That is why, this is becoming counter-productive.

Now, I come to certain other aspects of this Programme. I do not want to speak about labour participation in the production process. We have had sufficient questions in the House and we have seen how the Ministers are answering, how the whole thing is becoming almost a hoax. The Committee is powerless. The apex body is powerless. The Government had the cheek to come and tell the Parliament that 14 States, including the Union Territories—which, strangely, included Delhi also—refused to implement the decisions of the apex body. And they do not have any say in their apex body itself, and the Government only say: we are requesting. That is not the way it should be done.

Now, I come to the various concessions, the Government has given to the monopoly houses, big business houses, black-marketeers, and to the smugglers. There are opportunities to discuss it in the House, so I am just making a passing reference. The Voluntary Disclosure Scheme, whatever be the tom toming the Government is making, is nothing but a concession, a surrender the Government has made before the black-marketeers, who had made lot of black money in this country. Black money makers have been given a bonus, whereas Government refuse to give bonus to the working class.

Now, the abolition of bonded labour is one of the points on which the 20-point programme lays lot of emphasis. It is very good that the Home Minister himself has come when I am raising this pont. In Madhya Pradesh, where the Bonded Labour Abolition Ordinance has been promulgated, some people thought that it was necessary to go and propagate among the people about this. What has happened is this. Those who have gone to the villages to propagate this have been caught by the landlords, their heads have been shaved off, they have been put on a donkey back and taken out in a procession and the police register a case not against the lanlords, but against the victim, because he came there and created a sort of chaos there his is the way it was done. I am not ridiculing the whole thing; I know some good things have been done, but this has also happened. I would suggest that for the implementation of this, Government should take more stringent measures against those who are trying to scuttle this.

There was a news last week in the New Age about a Jan Sangh M.L.A. His daughter was married, a dowry was given; the dowry was not in money, not in ornaments, but in the form of a mate, who is a bonded labour. It was done; it is really so shocking. What are you going to do about this? This is our country where you have to implement 20-point programme. Unless, the Government takes a very serious view of the matter, nothing can be done.

Now, R.S.S. is banded. I said at the very beginning that we look at the banning of certain organization, declaration of Emergency and the 20-point programme as a package deal. RSS has been banned. Anand Marga has been banned, but I would like to draw the attention of the hon. Minister, especially Shri Brahmananda Reddy to this fact. You must have heard about Vijaya Bank, one of the biggest banks in this country. They are patronising a Union which is running almost like a Department of the Bank. This is manned almost ninety per cent by RSS people. The recruitment to the bank staff is not made through any other agency, but the Shakha's Chief

[Shri C. K. Chandrappan]

Sanchalak; their letter is only the basis of recruitment. I would bring a fact to the knowledge of the hon. Minister. The Joint Secretary of this Union which is affiliated to the Jan Sangh controlled BMS is under arrest; because he is an RSS man but the bank....

MR. CHAIRMAN: The hon. Member's time is up. Under the Rules there is a time limit. Nobody can speak on a Private Member's Bill for more than 15 minutes. But I have given you more than that. Please conclude now.

SHRI C. K. CHANDRAPPAN: I will just mention only one more important point.

This RSS man who is under arrest has been given leave by the Bank. He is in jail on leave provided by the Bank. Another RSS Union leader who has gone under-ground is on leave provided by the Bank. Is this the way you are implementing the emergency and the 20-point programme? I wonder about it.

Now, I am coming to the last point because the time is very limited. How can you do it successfully? That is a point to be thought about. Unless you make a democratic machinery at every level, especially at the grassroot level in which you involve all those people who are interested in the implementation of the programme, there is no guarantee that this programme will be implemented successfully. There is no guarantee. Now, the Government is heavily depending itself for the implementation on the bureaucracy. That is why, I think, they are faced with such consequences.

Lastly, the work at the grassroot level to make the people aware of the need for implementing this programme, should be done in a very systematic manner. Unless this is done, the 20-point programme also will meet the same fate as that of many other programmes announced in this country. A programme is an expression of a desire, an expression of a wish, but it needs organizational guarantee and democratic guarantees for successful implementation. No organizational and no democratic guarantee has been provided so far by the Government. This is one of the serious drawbacks that the Government should overcome. This is all I would like to say.

MR. CHAIRMAN: Sardar Swaran Singh Sokhi—he is not here.

SHRI D. N. TIWARY.

श्री डी० एन० तिवारी (गोपालगंज) : 1971 के चुनावों में हम लोगों ने जनता के साथ एक वादा किया था कि हम गरीबी मिटायेंगे । लेकिन शासन तंत्र में कुछ ढिलाई आई और उसका नतीजा हुआ कि सभी क्षेत्रों में डिसिप्लिन कम होता गया ? लड़के स्कूलों कालेजों में ठीक समय पर नहीं जाते थे, प्रोफ़ेसर ठीक से पढाते नहीं थे, फक्ट्रियों में काम करने वाले ठीक समय पर काम पर नही जाते थे और यहां तक कि सरकारी दफ्तरों के कर्मचारी वे भी ठीक समय पर दफ्तर नही जाते थे । ऐसी भीषण परिस्थिति हो गई थी कि देश कहां जाएगा, समझ में नही आता था । उस वक्त प्रधान मंत्री ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर देश को बचाने की कोशिश की और साथ ही लोगों के फायदे के लिए, देश को आगे बढाने के लिए बीस सूत्री कार्यक्रम देश के सामने रखा । अभी आल राउंड इम्प्रूवमेंट कुछ न कुछ हुआ है । किसी क्षेत्र मे ज्यादा हुआ है, किसी में कम । ऐसी बात नही है कि इम्प्रूवमेंट न हुआ हो, डिसिप्लिन न आया हो । देश का उत्पादन बढ़ गया है, कहीं दस परसेंट कहीं पद्रह और कहीं बीस परसेंट । चीजों की कीमतें भी गिरी है । पहले जहा अन्न बहुत महगा मिलता था उसके दाम अब सब से ज्यादा गिरे हैं । इससे किसानों को कुछ तकलीफ जरूर हुई है । लेकिन जैसा हमारे प्रस्तावक महोदय ने कहा है जो फैक्ट्री गुड्ज है और जो किसानों की गुड्ज हैं इन सबका समन्वय करके नइके दामों को ठीक किया

जाता तो किसानों को भी फायदा होता और देश भी आगे बढ़ता ।

20 सूत्री कार्यक्रम आगे बढ रहा है, यह ठीक है लेकिन जैसा प्रस्तावक महोदय ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि विलेज लैवल, ब्लाक लैवल और डिस्ट्रिक्ट लैवल पर यह काम धीरे से चल रहा है और कही कही तो शून्य के बराबर है । विलेज लैवल पर आपात्काल की स्थिति का ज्ञान बहुत लोगों को नही है । वे जानते है कि आपात्काल की घोषणा हुई है लेकिन उसमे क्या करना चाहिये, किस तरह से आगे बढना चाहिये, यह ज्ञान ही नही है और न अफसरान उसकी ओर ज्यादा तवज्जह देते है ।

20 सूत्री कार्यक्रम मे और सब प्रोग्राम तो चल रहा है लेकिन 2, 3 बात की खामिया जरूर है और वह यह है कि रीजनल डिसपैरिटी कम नही हो रही है । एक ही स्टेट मे कुछ जगह ऐसी है जहा बहुत गरीबी है और कुछ जगह ऐसी है जो ज्यादा खुशहाल है । स्टेटवाइज भी देखा जाये तो कुछ स्टेट ऐसी है जो कुछ अधिक सम्पन्न है और कुछ पिछडे हुए प्रदेश भी है जिनकी तरक्की हो नही रही है । वहा अन-एम्प्लायमैंट अधिक है । वहा लोगों की पर-कैपिटा इनकम भी बहुत नीची है । देश के सब अग बराबर तरक्की कर सकें, इस तरफ ध्यान कम दिया गया है । यदि देश मे कोई अग कमजोर होता है तो उसका असर सारे देश पर पडता है । जैसे शरीर के एक अग मे खामी हो तो, वह कमजोर हो तो शरीर ठीक से काम नही करता वैसे ही देश के साथ भी है । अगर देश का एक अग कमजोर रहेगा तो समूचे देश को पीछे खीचेगा, आगे नही बढने देगा । इसलिये गवर्नमेंट को सबसे पहले देखना चाहिये कि किन इलाकों मे कितनी गरीबी है और कितने लोग पीछे है और उनको किस तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिये ।

यह ठीक है कि प्रत्येक स्टेट्स् मे जो सदस्य आये हैं वह अपनी अपनी स्टेट के लिये मांग करते है और चाहते है कि अधिक से अधिक सहायता उन्हे मिले । लेकिन गवर्नमेंट को चाहिये कि वह देखे और समन्वय करे कि जो पिछडी हुई स्टेट है उनको आगे बढाने मे अधिक देने से वह और प्रदेशों के बराबर आ सकेगा है । यदि यह नही हुआ तो 20 सूत्री कार्यक्रम का असर उतना उन प्रदेशों मे या अन्य स्थानों पर नही होगा जितना और स्थानों पर होगा । पिछडी जगह बराबर पीछे होती जायेगी और आगे वाले आगे बढते जायेगे ।

इस 20 सूत्री कार्यक्रम मे जो पहले की स्कीमे हाथ मे ली हुई है, जो 10 12 या 15 साल से पडी है और उनका इम्प्लीमैंटेशन पूरा नही हुआ और जिनका काम बहुत धीमे चलता है, उन्ही स्कीमों को हाथ मे लेकर जल्दी से जल्दी कार्यान्वयन करना चाहिये जिससे उस स्कीम से जनता का जो फायदा होने वाला है वह हो और देश की आमदनी भी हो । इसमे दो बाते होती है । जिस स्कीम को हाथ मे लिया गया है, उनको पूरा न करने से उनका खर्चा बढता जाता है और लोगों का तस्दुद बढ जाता है । जैसे बिहार मे गण्डक प्रोजेक्ट है, वह 15 बरस मे कार्यान्वयन के लिये पडा है । वह 64 करोड की स्कीम है लेकिन अब उसका खर्च 200 करोड़ पर चला गया है । 136 करोड उसकी कीमत बढ़ गयी है । इसमे देश को हानि हो रही है और इतनी नही जो जमीन इसके लिए ली हुई है किसानो से वह भी 15 बरस से बिना किसी पैदावार के पडी है । अगर बिना सिचाई के भी अनाज वहा पैदा किया गया होता तो लाखो मन पैदा कर सकते थे । यह 10 हजार एकड से ज्यादा रकबा है । ऐसी स्कीमों को चाहे जिस प्रदेश मे भी हों, उनको पहले पूर्ण करना चाहिये । क्योंकि उनका काम शुरु हो चुका है ।

[श्री डी० एन० तिवारी]

जहां तक बिजली के उत्पादन और खर्च का सम्बन्ध है, हर प्रदेश के अलग-अलग आंकड़े हैं। उदाहरण के लिये मद्रास में बिजली की खपत प्रति व्यक्ति 100 यूनिट है जब कि नार्थ बिहार में 10 यूनिट है। गवर्नमेंट को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि नार्थ बिहार में भी बिजली की उपलब्धि ज्यादा हो सके। आप स्वयं महसूस कर सकते हैं कि जिस क्षेत्र में बिजली की कनजम्पशन 10 यूनिट प्रति-व्यक्ति है वहां क्या तरक्की हो सकती है? गवर्नमेंट जो नई नई बिजली के कारखाने बनाती है, उस में भी तथा-कथित समृद्धशाली प्रदेशों को तरजीह दी जाती है, जब कि पिछड़े हुए प्रदेशों की अव-हेलना की जाती है।

मैं प्लानिंग मिनिस्टर से कहूंगा कि वह सारे देश के लिए एक इनटेग्रेटिड एपरोच रखें और देखें कि कहां कम है और कहां अधिक है। यदि नार्थ बिहार एक बार मद्रास के बराबर नहीं आ सकता है, तो कम से कम उस की 10 यूनिट प्रति-व्यक्ति कनजम्पशन को बढ़ा कर 25 यूनिट या 30 यूनिट तो किया जाये। वहां बिजली के कारखाने खोले जायें, ताकि लोगों को अधिक बिजली मिल सके। आज-कल बिना पावर के कोई तरक्की नहीं हो सकती है। अगर सरकार हम को पावर नहीं देगी, तो हम कैसे तरक्की कर सकते हैं। वहां नार्थ बिहार में कोई इंडस्ट्री भी नहीं है, वहां केवल खेती होती है। इसलिए वहां पर भयानक अनएम्प्लायमेंट है और वहां अधिक ग़रीब लोग मिलते हैं। उन की परकैपिटा इनकम 125, 130 रुपये है, जब कि पंजाब और हरियाणा में पर-कैपिटा इनकम 800, 900 रुपये है। इस स्थिति में उन लोगों का जीवन-यापन कैसे हो सकता है?

यू० पी० के भी कुछ इलाके हैं, जैसे बलिया और गोरखपुर, जिन की दशा भी नार्थ बिहार जैसी है। इस रिजन की आबादी पांच करोड है। वह देश की जनसंख्या का 9 परसेंट है। इसलिए उन लोगों का हिस्सा उन को देना चाहिए और नेशनल इनकम का 10 परसेंट वहां खर्च करना चाहिए। लेकिन वह भी नहीं होता है। उन को केवल 2, 4 या 5 परसेंट किया जाता है। इस तरह वहां भी तरक्की कैसे होगी?

कहा जाता है कि बैंक बेकवर्ड एरियाज में खोले जा रहे हैं। बैंक खोलने के माने ये हैं कि वहां के लोगों को सुविधा मिले। लेकिन बैंक ऐसी जगह खोले जाते हैं, जो बैकवर्ड एरिया नहीं, बल्कि मोर फेवर्ड एरिया कहे जाने चाहिए। परिणाम यह है कि बैकवर्ड एरियाज के लोग बैंकों से कोई लाभ नहीं उठा सकते हैं। उन को समय पर पैसा नहीं मिलता है, जिस को वे खेती या छोटे छोटे रोजगार आदि में लगा सकें। इसलिए बैंक उन एरियाज में खोले जाने चाहिए, जहां के लोग ज्यादा पिछड़े हुए हैं। मैं मानता हूं कि पिछड़े हुए लोगों से बैंक को कम आमदनी होगी। लेकिन सरकार को तो लोगों की तरक्की करनी है। इसलिए उस को कुछ कम आमदनी होने से ज्यादा चिन्ता नहीं होनी चाहिए।

जहां हमारे देश में कृषि पर भार 76 परसेंट है, वहां बिहार में 85 परसेंट है। आप ही बतायें कि नार्थ बिहार में इतनी अधिक जनसंख्या कृषि के द्वारा अपना जीवन-यापन कैसे कर सकती है। आप नार्थ बिहार के किसी गांव में चले जाइये। आप देखेंगे कि वहां कितनी भयानक गरीबी है। लोगों को दो दो तीन तीन टाइम पर तो खाना मिलता है। ऐसी हालत में 20 प्वाइंट प्रोग्राम लागू करने का मतलब होना चाहिए कि इन रीजन्स को भी आप आगे ला सकें।

MR. CHAIRMAN: You began with the regional imbalance. You are now repeating the same point.

SHRI D. N. TIWARY: I want to show here that they all depend on agriculture and there is no industry.

MR. CHAIRMAN: You have stated that already.

SHRI D. N. TIWARY: Sometimes repetitions do happen. And every speaker does that.

SHRI ERASMO DE SEQUEIRA (Marmagaon): Repitition is no crime.

श्री डी० एन० तिवारी : एक बात मैं और इस संदर्भ में कह कर मैं खत्म करूंगा । वह यह कि एमर्जेंसी का प्रयोग कैसे हो रहा है । मैं ने प्रधान मन्त्री को भी एक पत्र लिखा था कि इस का दुरुपयोग भी बहुत हो रहा है और एमर्जेंसी में खास कर पुलिस और सप्लाई विभाग की पावर बहुत बढ गई है । उस पावर के बढने से ये पुलिस वाले और सप्लाई विभाग वाले लोगों को दिक करते हैं,लोगों को नाहक धमकाते हैं कि तुम को मिसा में भेज देंगे, डी आइ आर में बन्द कर देंगे । आप के सामने ऐसी कोई बात आवे तो आप उस की जांच करवा लें क्योंकि बदनामी आप की होती है । जो आफ़िसर ऐसा दुरुपयोग करते पाए जांय उन को कड़ी से कड़ी सजा दी जाय । मैं मानता हूं कि इस में एग्जैजरेशन होता है लेकिन होममिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, मैं उन से यह कहना चाहता हूं कि इस का दुरुपयोग भी होता है ।

अन्त में मैं यही कहूंगा कि 20 प्वाइंट प्रोग्राम का पार्शियल सकसेस हुआ है लेकिन इसे पूरा सकसेसफ़ूल बनाने के लिए एक इंटीग्रेटेड प्लान आप को बनाना होगा ।

SHRI S. P. BHATTACHARYYA (Uluberia): Mr. Chairman, firstly, I want to tell the House that a Congress Leader has published a book which has been addressed to the Congress workers on the Twenty-Point Programme. But, that has been done by a Government organisation. I think the leaders are thinking that whatever is published by the Congress Party is similar to one done by the Government. And whatever is passed in Kamagata Marunagar is also passed here. Then what is the use of this Parliament? The Congress Party runs the Government here. You are taking the position that since you are in power and you are in a majority, you take it that whatever the party's decision is Government's decision. It is correct? And then you are propagating the Twenty-point Economic Programme to the people. This twenty-point programme has come now after 27 years of independence. Repeatedly you have been telling the people that you would solve the day-to-day problems of the people—poverty, unemployment and everything else. Repeatedly promises have been made in this regard. It is after twentyseven years of independence that the Prime Minister is saying that the twenty-point programme is to be implemented seriously to solve the problems. Then why nothing had been done so long. You declared the twenty-point programme, but there is nothing against the multi-national cartels or monopolists or even against the big landlords who are keeping their fallow lands and are minting money. Nothing has been said about them. But declaration had also been made that there would be no more nationalisation, and a claim has been made that this twenty-point programme will solve all the problems with the people's cooperation.

Sir I come from an area—partly industrial area; you are declaring that the workers' cooperation will be taken in running the factories. But the owners of mills and others are closing down the factories and the workers are thereby thrown out of employment and nothing has been done. The West Bengal Labour Minister says that he can do anything. Look at the thing that the Birla factory I.P.L. (Machine Tools) still remains closed; for months together the workers are starving and in Prem Chand jute mills. suddenly the mill owners declare lay-off and 1200 workers were thrown out of employ-

[SHRI S. P. BHATTACHARYYA]

ment as a result. Nothing has been done about it. Take the case of Jetia cotton mills where 1200 employees were thrown out of employment and they are now starving and their arrears have not yet been given. Now, you declare that there should be cooperation of the workers and owners in running the industry but this is the practice going on. In the rural areas as regards the question of land distribution, are the 'khas' or benami lands properly recorded? The reports taken by the 26th round of National Sample Survey which you have recently published or the agricultural census are taken orally from the big owners and that oral answer is the basic ground on which you are deciding as to how much land is owned by the big land owners and how much is available for distribution amongst the landless agricultural labourers.

According to the records in Bihar you will find mostly there is no surplus or benami land but on 10th January, the Bihar paper, Searchlight published a report that one big land owner has sold illegally nearly 2,000 to 3,000 acres of land. The Magistrate after hearing the case decided that all the transfers were false and illegal. You are taking the record from such persons and placing the same before the FAO and on the basis of that you are giving information to us.

As regards land distribution being done in West Bengal. I can tell you that there are cases where the land committees are formed by the Congressmen who are, fortunately or unfortunately, themselves big landlords. These people have distributed 'khas' lands among their relations. Whereas the wife of a panchayat pradhan is getting the land the landless peasants are not getting any land.

You know in the villages homesteads with an area of 2 cents are being given. After this kind of homestead is given the land committee has decided to fix the land in some cremation ground or somewhere at a distance of five to six miles. These persons to whom the land is given were residing earlier in the land of big owners. After the land is allotted the poor peasant's hut is broken and he is driven out from there. Now, is it giving him the land or throwing him out of the land? Legally it is said that eviction should be stopped but I can tell you in Birbhum and in other areas the big land-owners are illegally throwing out the share-croppers, cutting away his crop and with the help of the police getting the 'burgadar' arrested. The landowner is so powerful that he can put pressure upon the SDOs, SPs and other Police officers and they cannot do anything. how are you going to implement land distribution? Is it possible?

Coming to agricultural wages, even the minimum wage fixed is not paid. Who is going to see to it that it is paid? I asked the BDO in my village: 'How are you going to implement it?'. He said: 'If an agricultural labourer comes with a complaint that particular owner is not giving the minimum wage, then I can arrest the owner. But what next? If I arrest the owner, some other agricultural labourer will come and work at a lower wage and the other man will only lose his job'. What is the good of that? So nothing is done. How can it be implemented? Only with the organised co-operation of the rural people can it be implemented. This Government has been running the country for years together. The main thing must be understood. Rajani Palme Dutt had said in *India Today* that there was no land-less peasant in our country before British rule. What is the position now? The rural people are thrown out of their land. They become landless and homeless. They become bonded labour; they become slaves to the moneylender. What is the background for that? What is the economic basis for that? That is the main thing to be studied. Without eliminating the basic cause which compels the poor people to surrender the moneylenders,

nothing can be solved. That is the basic problem. So our suggestion is that the big owners owning above 4 hectares of land who are not themselves cultivators should be tackled; all that land should be taken over and distributed among the landless poor peasants, tribal people and Scheduled caste people, by elected peasants committees. Those cultivators must be helped with irrigation facilities, fertiliser, loans, good seeds etc. Then the enthusiasm can be created among them. But I think this is not the purpose of the Government, to really solve the problem of the rural poor this way. I am definite about this experience of various countries has already proved that a redical land distribution policy, of distributing land to the real tillers can only win their co-operation. This cannot be got by bureaucrats doing this and that. Only this policy can create real enthusiasm among the rural people, can create development of our production, can create sufficient markets for the rural people and can create a good home market for our industrial development. Only this way can we wipe out our unemployment problem. This can be done in our country. The real materials are there in our country for doing this. But you are not proceeding in this direction. You are proceeding in a different way, supressing the people and asking them to co operate. But no co-operation of the peop e is allowed.

MR. CHAIRMAN: You please co-operate with me. The time is up.

SHRI S. P. BHATTACHARYYA: I am co-operating. You co-operate with me. At the Pugwash conference, our Prime Minister said that justice should be established in the international field, otherwise peace cannot be established throughout the world. If that is true of the international sphere, our Government must clearly see to it that Government does justice to the people here that every person will get either land or work, the right to live and exist and not be compelled to starve or be exploited or girls driven to prostitution, girls to become prostitutes or become bonded labour. Such a situation can be created in our country where real justice can be done to the people. The basic thing is this. Our ministers have been telling about feudal exploitation, land owners exploitation in the village rule, that must be totally obliterated and cleared by people's co-operation. That is the only way, without that you cannot proceed any further. Nothing will solve the problem; nothing will make headway towards better life, if that is not done. The other day in Calcutta our people wanted to commemorate the death of Mr Chou En-Lai who removed from his country poverty and unemployment. They wanted to hold a mass meeting but that was not allowed. Is this democracy or justice. Is it on that basis you want people to build a new India?

17.00 hrs.

MR. CHAIRMAN: Mass meeting is not held even there.

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, 20 सूत्री कार्यक्रम में आर्थिक न्याय दिलाने के लिए एक योजना है और यह प्रोग्राम लोकतन्त्र को टिकाने के लिए एक जादू है और जैसा कि श्री शंकर राव चव्हाण ने कहा है कि यह माडर्न भागवद् गीता है। कुछ भी नाम लीजिए लेकिन सवाल यह है कि इस की क्रियान्विती कैसे हो। जो प्रस्तावक महोदय हैं, जिन्होंने संकल्प रखा है, वे बडे न्यायवद्ध अनभवी ससंद सदस्य हैं। उन्होने कहा है कि हिन्दुस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक इस का जितना प्रचार हो रहा है और बड़े जोरों से प्रचार हो रहा है उस का उतना ही पालन नही हो रहा है। यह कार्यान्वित हो रहा है या नही, इस के बारे में मैं बार बार सोचता हूं और मैं समझता हूं कि इस प्रोग्राम को इम्पलीमेंट करने के लिए हमें तीन बातें सोच लेनी चाहिए।

[श्री मूल चन्द डागा]

पहली बात यह है कि प्रोग्राम को इम्पलीमेंट करने वाले जो औजार है, जो हथियार है, वे कमे है । आज सारा प्रशासन तन्त्र जड है, वह मानवता से शून्य है और मानवता से शून्य प्रशासन तन्त्र म चेतना नही होती । ऐसे प्रशासन तन्त्र मे गरीब जनता न्याय नही पा सकती । इसलिए एक बात तो मैं यह चाहता हू कि आप न्याय दीजिए । एक दफा हमारे होम मिनिस्टर साहब, श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी जी ने कुछ इस्ट्रक्शन्स निकाले थे और वे इस्ट्रक्शन्स ये थे कि गरीबों की जो शिकायत हो, उन का निराकरण किया जाए । बहुत सुन्दर बात थी और अखबारों मे भी वह निकली थी लेकिन आज सब से बडा सवाल यही है कि गरीब लोग अपनी शिकायत लेकर जिस दरवाजे पर जाते है वहा उन को न्याय नही मिलता और जब न्याय नही मिलता, तो शासन म कमजोरी आती है । आप कुछ न करिये बल्कि यह कर दीजिए कि तहसीलदार, कलेक्टर सिविल कोर्ट जहा कही भी न्याय मिलना चाहिए वहा पर लोगों को न्याय मिले । आज ऐसा नही होता है और कुछ चन्द लोगों ने न्याय का रोक रखा है, एक तो पूजीपतियां ने और दूसरे बड़े शक्तिशाली लोगों ने आप गावों मे देखिये । वहा पर कुछ मोटे मोटे जमीदार है, जिन के पास पैसा है, जिन्होने अपना राज जमा रखा है। सारा शासन वह करते है और गरीबों को न्याय नही मिलता । इसी तरह से शहरा मे भी, बम्बई जैसे शहर मे भी दस-बीस बडे बडे आदमी राज्य करते है । जहा जहा भी ऐसी प्रतिगामी शक्तिया है उनको कुचला जाना चाहिये । पुलिस भी क्या करती है । वह भी ताकतवर जो हैं उन से मिली रहती है, जो पैसे वाले है उनके एजेंट के तौर पर काम करती है । आप कहते है कि जमीने आपने बेजमीन लोगों को दी हैं । लेकिन कब्जा कौन उनको उन जमीनों का दिलाएगा । पुलिस भी उनको नहीं दिलाती है क्योंकि उसका सम्बन्ध गांव का जो गरीब आदमी है उससे है ही नही । दुनिया मे दो चीजों की आज भी इज्जत है । धन की प्रतिष्ठा है और जो मनुष्य आगे बढ़ा हुआ है उसी की महिमा है । समाज मे आखिरी पंक्ति पर जो खडा है, जिस का हाथ मैला है, जिस का मन साफ है उसकी इज्जत नही है । उसके लिए केवल बाते ही बाते हैं । जब नेता लोगों का स्वय का आचरण ठीक न हो तो उनकी बात का दुनिया मे क्या असर पडेगा । समाजवाद की बात अगर की जाएगी लेकिन उनका आना जाना, रहन सहन ऐसा होगा जो पूजीवादी होगा तो दुनिया पर उनका प्रभाव नही पड सकता है । बडे लोग बडे अच्छे तरीके मे बात करना जानते हैं, बडी अच्छी अग्रेजी और हिन्दी बोल लेते है, शानदार तरीके से बोलना जानते ह उन के कहने का किस तरह से कोई असर हो सकता है । जो खुद कुतुब मीनार पर बैठे हुए है वे जब जमीन पर आ जाएगे तब जमीन पर बैठा हुआ जो आदमी है वह ऊपर उठ सकेगा । जो कुतुब मीनार पर बैठा हुआ आदमी है वह ऊपर और ज्यादा बैठना चाहता है तो किस तरह से समाजवाद आ सकता है । बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत न्याय तभी मिल सकता है जब हमारे मन्त्री और हम लोग सरप्राइज चैक करे, गाव गाव के अन्दर इनकाग्निटो जाए भेष बदल कर जाए, वहा घूमे तब हम मालूम पडे कि वास्तविक स्थिति क्या है और उसका किस तरह से निराकरण किया जा सकता है । गरीबों की आखों के आसू पोछे, उनकी उदासी को मिटाए । एम०पी० की वहा पावर कोई नही है । दिल्ली यूनिवर्सिटी का निकला हुआ आई०ए०एस० जो कलेक्टर है जिस को अभी शादी करनी है उसको कलेक्टर बना कर भेज दिया जाता है, जो कुछ जानता नही है, उसी के पास सब पावर्ज केन्द्रित हैं । पच्चीस साल से जो काम करने वाला एम पी है उसकी कोई पावर नही है, एम०एल०ए० की कोई पावर नही है, और जो पच्चीस साल का लडका कलेक्टर

है, जो रेवेन्यू ला का जानकार नहीं है, जो उसको बिल्कुल समझता नहीं है, जो साफ सुथरा रहना जानता है, जो अच्छी परसनैलिटी का मालिक है, जो खूबसूरत जरूर है, किन्तु जानता कुछ नहीं है, लेबर ला नहीं जानता है और जो ठीक समय पर कैसे आया जाए, यही जानता है और अनुशासन के नाम पर तो यह ठीक बात है लेकिन जो काम करने वाला नहीं है वही वहां का मालिक है। वहां काम करने वाले आदमी जाने चाहिये। जो पुराने काम करने वाले संसद् सदस्य हैं, जो एम एल एज़ है उनको आप अधिकार दें। ऐसा आपने किया तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होता है। उसको यह पता है कि प्रोमोशन कैसे मिलता है। वह दो तरह से मिलता है। जब मिनिस्टर आवे तो उसका खूब स्वागत करें, उसको अच्छा खाना दे, रात को कल्चरल प्रोग्राम आर्गेनाइज कर दे। जो काम करने वाले है, जिन्होंने जिन्दगियां दी हैं, खेतों में, खलिहानों में, जिन्होंने मजदूरों के अन्दर काम किया है उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। कलेक्टर के पास ही सब पार्वज है। मिनिस्टर बेचारा बेसमझ है, वह भी पढ़ा लिखा हुआ नहीं होता है। मिनिस्टर होशियार हो तो बात को पकड लेगा और कलेक्टर को कहेगा कि अलग हो जाओ। कई बार देखा गया है कि रेवेन्यू ला को इम्प्लेमेंटेशन करने में तकलीफ होता है क्योंकि उसको जानने वाला न कलक्टर होता है और न मिनिस्टर। मिनिस्टर ने उसको स्टडी नहीं किया होता है। वह सेक्रेटरी आदि पर डिपेड करता है। उसको कहता है कि कलेक्टर ने यह कहा है मुझे तुम बताओ। इस वास्ते आवश्यकता इस बात की है कि प्रतिगामी शक्तियों को आप कुचलें। एक श्री नगेन्द्र प्रसाद यादव हमारे मेम्बर हैं। अखबारों में खबर आई कि उन्होंने बहुत जोरदार भाषण किया बीस सूत्री कार्यक्रम के पक्ष में। उन पर लठैतों ने हमला किया। पुलिस ने कहा कि तुम गुनहगार हो, तुम डकती मारने गए थे। यह प्रशासन तंत्र इतना निकम्मा साबित हुआ है कि यह देश की प्रगति में बाधक सिद्ध हुआ है। इस में सेवा भाव नहीं है। ये गर्दन ऊंची किए बैठे रहते है और कोई एम०पी०० आ जाता है तो मिनिस्टर तो मेहरबानी करके खड़ा हो भी जाता है लेकिन ये खड़े नहीं होते है और चाहते है कि जितनी जल्दी यह निकल जाए उतना ही अच्छा है। सरपंच चला जाए तो न तहसीलदार खड़ा होता है और न ही कलक्टर।

योजना मंत्री बैठे हुए है। योजनाओं का क्रम 1952 में शुरु हुआ था। देश का जो आखिरी अंग है, समाज का जो आखिरी अंग है जिस के घर पर न दिया जलता है उसको आशा बंधाई गई थी कि उसके घर पर दिया जलेगा और लोगों में नई जागृति आएगी, जागृति का डंका बजेगा। गांवों का दुर्भाग्य है कि पुलिस ने और सरकारी अधिकारियों ने लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया है और उनको विश्वास होता गया है कि उनको न्याय नहीं मिल सकेगा।

हमारे घर पर दीवाली के दिन मिठाई उड़ रही हो और लडके की शादी पर 500 आदमी आ रहे है तो यह देखकर गरीब आदमी सोचता है कि इस को शूगर कहा से मिली है, घासलेट कहा से मिली है। मिट्टी का तेल इसे कहा से मिला है, क्या काले बाजार से लाया होगा।

17.10 hrs.

(Mr. Speaker in the Chair.)

आवश्यकता इस बात की है कि प्रशासन से भ्रष्ट अधिकारियों को निकाला जाये। आज परिस्थिति यह है कि कलेक्टर जनता की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देता है। थानेदार रात को शराब पीता है। उन लोगों को अनुभव करना चाहिये कि वे 24 घंटे के लिए सरकार के नौकर है।

[श्री मूलचन्द डागा]

ऐसे अधिकारियों के होते हुए छोटे लोगों को राहत कौन देगा? मैंने बार बार कहा है कि सरकार भले ही और कुछ न करे लेकिन वह ऐसी व्यवस्था करे कि गरीब आदमी की शिकायतों को सुनकर उनका तुरन्त समाधान करने की व्यवस्था हो। कलेक्टर के पास जब कोई शिकायत की जाती है तो वह उसको तहसीलदार या एस० डी० ओ० के पास फारवर्डेड फार "नेसेसरी एक्शन" लिखकर भेज देता है और इसके बाद कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। जहां तक मन्त्रियों का सम्बन्ध है वे लिख देते है कि आपका पत्र मिला, मैं मामले की जांच कर रहा हू और वहीं पर बात खत्म हो जाती है। यह जरूरी है कि जो व्यक्ति अपनी समस्या लेकर आये, उसका निराकरण शीघ्र किया जाये।

अगर कोई एम० पी० झूठी शिकायत करता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है आज इस बात की भी बहुत जरूरत है कि बड़े बड़े नेता लोग समाजवाद के ऊंचे मीनार से उतरकर नीचे आ जाये।

जहां तक बैंको का सम्बन्ध है गांव का छोटा आदमी बैंक से कर्ज नहीं ले सकता है। पटवारी कहता है कि मैं तसदीक तब करूंगा जब मुझे 5 रुपये का नोट देगा। इसी तरह तहसीलदार 20 रुपये मांगता है।

श्री चन्द्रप्पन बड़ी सुन्दर अंग्रेजी में भाषण देते है मगर शायद यह नहीं जानते कि गांव में काम करने वाला कौन है? आज हमारे देश में गरीब लोगों की मदद कौन करेगा। हम एम० पी० है हमें यहां भाषण देना है और कई बड़े काम करने है। हमें उन लोगों की समस्याओं से कुछ मतलब नहीं है। श्री माठ इन्टरनेशनल आदमी बनना चाहते है। हम देखते है कि जिस व्यक्ति की गांव में इज्जत नहीं है, उसको शहर में पूजा जाता है और जिसकी अपने देश में कोई इज्जत नहीं है, वह अन्तर्राष्ट्रीय इज्जत प्राप्त करने की कोशिश करता है।

योजना मंत्री इस बात की तरफ ध्यान दें कि छोटे छोटे लोगों के पास पहुंचना और उनकी समस्याओं का निराकरण करना चाहिये। श्री पाई और श्री सुब्रह्मण्यम कहते हैं कि बैंक पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं। क्या यह बात उनको अब मालूम हुई है? गरीब आदमी को बैंक से ऋण मिलना मुश्किल है। मनीलैंडर उसको पैसा देते नहीं है। नतीजा यह है कि न इधर के रहे और न उधर के रहे, न खुदा ही मिला न वसाले सनम" सरकार बैंक खोलने की व्यवस्था करे, मनीलैंडर अपने आप भाग जाऐंगे।

जहां तक को-आपरेटिव्स का सम्बन्ध वह बड़े लोगों के हाथ में है। कोई किसी एम० पी० का रिश्तेदार है और कोई किसी अन्य मेम्बर का आदमी है। वहां पर लोग लाखों करोड़ो रुपये खा गये हैं। मगर एक केस भी रजिस्टर्ड नहीं हुआ। जब हम स्वयं चरित्र से खाली हैं तो समाजवाद के भाषण देने से क्या लाभ होगा? राजस्थान में 1959 में सीलिंग ला पास हुआ था। मगर आज 1975 में भी जमीन नहीं दी गई हैं। इस बारे में जो कमेटिया बनाई गई हैं, उसके मेम्बर भी बड़े बड़े लोग है। 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में काफी फोटो निकलेंगे और बहुत प्रचार किया जायगा कि सारा काम हो गया है। आज इस बात की आवश्यकता है कि पब्लिसिटी पर ज्यादा जोर न देकर जिन लोगों की आखों में आसू है, उनको कुछ राहत दी जाय। जो गरीब लोग है, बिल्कुल नदी के किनारे या तालाब आदि के पास उनको जमीन और मकान दिये जाते है, जिससे उनको इस योजना का कोई लाभ नहीं हो पाता है।

सरकार को ब्लैक मनी के डिस्क्लोजर के द्वारा ढाई अरब रुपये मिले है। मेरा निवेदन है कि सरकार को यह रुपया बिजली और सिंचाई के काम में लगाना चाहिये। जहां तक मकान का सम्बन्ध है, ठेकेदारों से मकान

बनवाये जाते है और ठेकेदार एक कोठरी बनाने के लिए 400 रुपये लेता है और 600 रुपये खा जाता है। इससे अच्छा यह है कि गरीब आदमी को रुपया दिया जाये ताकि खुद कच्चा मकान खडा कर ले। फोटो आते है कि हरिजनो के लिए मकान बन गये, मगर ऐसे मकानो मे हरिजन कैसे रहेगे।

महाराष्ट्र मे एक इन्ट्रेस्टिंग प्रोग्राम बनाया गया है कि भले ही किसी की पूजी लाखो की हो, उसको कर्जे से मुक्त कर दिया जायेगा। सैंटर से गाइड लाइन्स दी गई कि रूरल आर्टिजन, फार्मर और लेबरर आदि को कर्जे से मुक्त किया जायेगा। लेकिन इसको इस तरह कार्यान्वित किया गया है कि जो कोई भी 500 रुपये तक कमाने वाला है, चाहे उसकी कितनी इम-मूवेबल प्रापर्टी हो, उसको कर्जे से मुक्त कर दिया जायेगा। जब सैंटर की गाइड लाइन पर इस तरह से कार्यवाही होती है तो देश मे अशाति पैदा होती है।

अन्त म मै यही कहूगा कि गृह मत्री को यह इस्ट्रक्शन्स देनी चाहिये कि गरीब आदमी जो शिकायत लेकर आये, उसका निराकरण किया जाय और उसको न्याय मिले। 20 सूत्री कार्यक्रम पर पूरी शक्ति और पूरे दिलो दिमाग से काम किया जाना चाहिये। लेकिन अगर मन के सकल्प मे छद्म हो, तो सफलता मिलना सभव नहीं है।

SHRI ERASMO DE SEQUEIRA (Goa) A very senior and respected Member of this House, Shri Bhuti Mishra has hit the nail on the head And I hope, Sir, for doing this, the head will not hit him on the nail, because he has pin-pointed one matter that this Government runs away from, one word, and that is "implementation" We are discussing the 20-Point Programme which according to the Congress is the basis of the ruling party of this country. And, Sir, the barometer of the lack of seriousness with which the Congress itself views this pronouncement, is the fact that as we discuss this measure in the House, the Congress benches are deserted, and we do not have in the House, as we discuss this economic programme, a single senior Minister from an economic Ministry I know that we have Mr. Gujral from Planning, but if you will forgive me for saying so, the Planning Ministry for many years has been devoid of economics. It is known to all of us, Sir, that since its birth, the New Congress has, time after time, come forward with something or the other, which it classified as the magic medicine for all the ills that plague this country. It began with the slogan 'garibi hatao'. What has happened to the advance of 'garibi' in the country since then, is no secret to anybody. An hon. Member of the Congress Party has just put forward, in a much better way than I could do, what has happened since then Then there was the 10-point programme Let me read out to you from the Working Committee resolution of the Congress Party

> "The Committee desires that a plan of rural works programme which would give opportunities for employment especially to the landless and at the same time help to create certain overheads in agriculture such as agro-industries, reclamation of land, soil conservation, afforestation, minor irrigation, feeder roads, cattle development and other programmes of area development should be formulated to be implemented"

What has happened? It was around 1970 The programmes were never even formulated leave alone being implemented It then says

> "Drinking water should be provided in all rural areas by a national programme of wells, conservation of water and utilisation of scientific methods"

[Shri Erasmo De Sequeira]

Where is the programme? Where are the wells? Where is the conservation of water? All down the drain. Then, Sir, there was a 10-point pledge It says:

> "The drive to spread knowledge will be given a new dynamism—with compulsory school education for every child up to the age of eleven by 1975 ."

This is 1975 What has happened? Have you made it compisory? It also says

> Steps will be taken to establish a gigantic national water grid by link up of all our major rivers from the Ganga in the north to the Cauvery in the south'

The one man who could have done it, Dr. K. L Rao, has been retrenched Mr Mishra's resoultion, Sir, requests that the adminisrative and legal hurdles in the way of the 20-point programme, should be removed What were the administrative and legal hurdles that came in the way of the implementation of the previous programmes that I have talked about? There were none All that I would say is the one basic fact that to day the entire country realizes is that this Government is unable to perform All it takes to produce a programme is a piece of paper and a fertile imagination To implement it, you know, is a completely different matter It is not a nice thing for any one of us to say this we are all in the same game, we were all elected to the House, they were all elected into the Government we were elected into the Opposition we would like to see them perform But not only did they not perform They are not even willing to admit it When were these programmes introduced *Garibi hatao* came on the eve of an election The 10 point programme came just after the party split. Now comes the 20-point programme, just after the alleged emergency, at the fag end of the term of this Government. What are we discussing today? What was the term that this Government was elected for? It expires on the 18th of March All that is happening is nothingmore than an attempt to detract attenion from the fact that the term of his Government is running out By all laws of logic and by all laws of democracy, they should now go back to the people and seek a fresh mandate It is no use to ignore they have not performed it is no use to ignore that if they go to elections in March, they will land upon this side of the House, where they deserve to be This is precisely why, in an attempt to continue to hoodwink the people of this country, they come forward with another programme which, I am sorry to say, I am convinced they do not intend to implement just like they have not implemented any of the previous programmes that were pledged before this country since the birth of the new Congress

How can anyone believe that this Government, and our present leadership want to deliver the goods to the common man? Look at their behaviour in office I will give you a recent example The President was in Goa early this week—and I am sure it will not surprise you Sir, because you have seen this happening all over the country—the roads were white washed with paint which would vanish before he left and lakhs of rupees were spent Traffic was stopped on the roads, hours before he passed The entire traffic on the river, the barge traffic for iron ore export and fishing traffic for food was stopped for hours, to enable the President to be taken on a twenty mmute cruise Here they say that we are a Government of the people, and the behaviour is of a monarchy, far worse than feudal

It is also no secret, I believe, that at the Western Regional Conference in Goa the hon Union Home Minister,

who happens to be in the House, tried his hardest to dissuade the Chief Minister of Gujarat from holding the panchayat elections. This is the extent to which this Government is interested in staying away from the people; because, it is very well known, once it goes to the peole, it will never be the Government; at the most, it will be an opposition.

Nobody can quarrel with any of the objections that lead to a better life for the people of our country. I would have been very happy if we had discussed this programme in the first week of this House in 1971. Then it would have been a meaningful discussion. Today it is nothing but and attempt to continue to mislead the people of this country.

I hope against hope that wise counsels will prevail and that the elections will be held on time, because, beyond the term of this House, this Government, if it remains, it can remain only as an usurper of power, because it has lost its mandate.

श्री बसंत साठे (अकोला): अध्यक्ष जी, आज यह जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव श्री विभूति मिश्र हमारे सामने लाये है, मैं उम्मीद करता था कि हमारे अपोजिशन के भाई, खासकर मेरे पूर्व जो बोले श्री सेकरा, वे इस बीस सूत्री कार्यक्रम के बारे में कुछ सुझाव देंगे। उस को अमल में लाने के बारे मे यदि कुछ ठोस सुझाव देते तो ज्यादा अच्छा होता। उन्होंने एक पोलिटिकल भाषण यहा कर दिया यह कहते हुए कि यह सारा जो कुछ है यह कांग्रेस पार्टी करना नही चाहती है। यह पोलिटिक्स है, और उन को यदि मौका मिलता तो सरकार बना लेते।

मेरा खयाल है कि जब हम 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में सोच रहे है तो खुले तौर से हमें अन्तर्मुख हो कर निरीक्षण करना चाहिये। यह प्रोग्राम खाली कांग्रेस का नहीं है, बल्कि सारे देश का प्रोग्राम है और इस में सब को सहयोग देना है और सब को इसे कामयाब बनाना है। यदि ऐसा करना है तो हमें देखना होगा कि इसको अमल में कैसे लाया जाय। सब ने माना है कि जो कदम है वह बड़ा अच्छा कदम है, जैसे जमीन मिलनी चाहिये भूमिहीन किसानों को, उन को रहने के लिए हाउस साइट्स मिलनी चाहिये। किसे शिकायत हो सकती है इस बारे में कर्जा माफ कर दिया तो कर्जा मिलना चाहिये अब यह होगा कैसे? मै कुछ सुझाव देना चाहता हू। माननीय जगा जी दुखी हो कर एक तरह से जिसे सात्विक गुस्सा कहते है, उस मे वह बोले, लेकिन उन्होंने भी कुछ ठोस सुझाव नही दिये।

मै यह कहना चाहता हू कि इस देश में 362 जिले है। इन मे अमल लाने के लिये आप को 362 ईमानदार पोलिटिकल काडर के लोग जो कांग्रेस के भी हो सकते है और बाहर के भी हो सकते है, क्या ऐसे आदमी आप को नही मिल सकते है? अक्सर तो जिम्मेदारी पार्टी की ही होती है जिस का कि प्रोग्राम होता है, कम्यूनिस्ट मुल्कों में भी और कैपिटलिस्ट मुल्को मे भी पार्टी की जिम्मेदारी होती है अमल मे लाने की। क्या आप के पास 362 आदमी नही है? एक एक जिले म एक एक आदमी रख दीजिये चाहे उसे कमिश्नर कहिये, इकोनामिक प्रोग्राम इमप्लीमेंटेशन कमिश्नर कहिये, या इकोनामिक कमिश्नर कहिये, एक एक जिले मे इन को नियक्त कीजिये। जहा तक इकोनामिक प्रोग्राम का ताल्लक है उस के इमप्लीमेंटेशन के लिये सारी ऐडोमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी उस के नीचे रहे और फिर कहिये कि तुम जिम्मेदार हो इसे इमप्लीमेंट करके दिखाओ। आप सहयोग लीजिये, कमेटिया बनाइये, वह लोगों का सहयोग लेने के लिये रेस्पांसिबिल होगा। बिना कोआपरेशन के यह प्रोग्राम कामयाब नही हो सकता। कहने का मेरा मतलब यह है कि आप पोलिटिकल काडर का आदमी एक एक जिले में रखिये और इस इकोनामिक प्रोग्राम को इमप्लीमेंट करने का

[श्री वसंत साठे]

उस का उत्तरदायित्व हो। वह फिर यह नहीं कह सकता कि मैं क्या करूं, कलक्टर मेरी मदद नहीं करता इस बारे में सरकार को क्या कहना है? क्या आप 362 आदमी नहीं चुन सकते पोलिटिकल काडर के जिन का यह उत्तरदायित्व हो और आप उन को कह सकें कि तुम चार महीने के अन्दर यह कर के दिखाओ?

No arguments or excuses will be allowed. This is what Sri Jawahar-Lal Nehru used to say. The time has come to do that.

तो एक सुझाव यह है।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि मशीनरी में आज क्या क्या लेकूना हैं, वे आप को देखने चाहिये और उन की तरफ मैं आप का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। 20 सूत्री कार्यक्रम के इम्पलीमेंटेशन में सब से पहला सवाल तो है लैंड सीलिंग का। लैंड सीलिंग में हुआ यह है कि, जैसा अभी हमारे मित्र डागा जी ने भी कहा, जिस के लिये लैंड सीलिंग करनी है, उन को कोई अधिकार नहीं है। सारी कमेटियों में कानून बनाने वाले और अमल में लाने वाले वही लोग है जिन की जमीन लेनी है। वे उस को लेने नहीं देते और कोई न कोई रास्ता निकाल लेते हैं जैसे कि कह दिया कि लैंड रिकार्ड बने नहीं हैं। यह बड़ी अजीब बात है कि इस देश में बिहार और यू०पी० में लैंड रिकार्डस नहीं बन पाये। जमीन पर जो आदमी काश्त कर रहा है, आखों से दीखता है कि वह उस पर काम कर रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि वहां पर पालिटीकल आदमी भेजिये और आदमी भेजते वक्त यह ध्यान रखिये कि एक राज्य का आदमी दूसरे राज्य में जायेगा। यह मत कहिये कि उसी राज्य का पालिटीकल आदमी उस राज्य में जायेगा वह वहां जायेगा तो कुछ नहीं कर पायेगा। केरल का आदमी पंजाब में भेजिये, पंजाब का आदमी बिहार में भेजिये, महाराष्ट्र का आदमी यू०पी० में और यू०पी० का आदमी तमिल नाडू में भेजिये। इस तरह से वहां भेजें और फिर आप देखियें कि एक दिन में काम होता है। जो किसान पीढ़ियों से एक जमीन पर काश्त कर रहा है, उस का वहीं का वहीं सारा रिकर्ड बन जायेगा। क्या मुश्किल है इस में अगर इरादा हो तो?

दूसरी होम-साइट्स की बात आप देखिये। सचमुच मुझे कभी कभी यह लगता है कि प्रोग्राम यदि ठीक से अमल में नहीं आया, तो बूमरेंग हो जायेगा, बैकलेश जिसे कहते हैं, वह हो जायेगा और जैसा कि श्री चन्द्रप्पन ने उदाहरण दिया कि हम जिन्हें होम-साइट्स देने जा रहे हैं उन्हें ही मकानों से उजाड़ दिया नाले में या और उन को फेंक दिया जमुना पार किसी नाले की जमीन में खुले में। अब कितना असंतोष उन के दिल में होगा, यह आप समझ सकते हैं। आज तो वे कुछ कह नहीं पाते लेकिन उन के दिल में बहुत असंतोष हैं और एक दिन कहीं वे भड़क न जायें। तो इस तरह का काम नहीं करना चाहिये।

लोग कहते हैं कि तुम बड़े स्वप्न की बात कहते हो। आप तमाम सिविल लाइस देख लीजिये। एक एक बंगले के इर्दगिर्द बीस बीस, दस दस और पांच पांच एकड़ जमीने हैं। ये सब मिनिस्ट्रों के बंगले हैं, बड़े बड़े अफसरों के बंगले हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि इन गरीबों की कोलोनीज यहां बना दें। अच्छी कलोनियां आप उन के लिए बनवाइये। आप स्वार्थ की दृष्टि से भी देखिये। उन को बहुत दूर फेंक दिया गया और आप को अपने घर पर काम कराने के लिये लेबर नहीं मिल रही है। 20 मील से वे आ नहीं सकते। इसलिये आप उन की कोलोनीज यहां बनाइये और अच्छी साफसुथरी कोलोनीज बनाये। गरीबों को आप यहां नहीं रहने देते। जब आप अमीर गरीब का भेदभाव मिटाना चाहते हैं, तो उन को यहां रहने दीजिये लेकिन जो हाउसिंग मिनिस्टर हैं, उनका जो कांसेप्ट हैं, उन के कांसेप्ट में

यह बैठता नहीं है (व्यवधान) यह तो होम-साइट्स की बात हुई। मैं खुद अपनी कांस्टीट्युएन्सी में गांवों मे दौरा कर के आया हूं और मैं ने प्लानिंग कमीशन में भी कहा था—मैं गुजराल साहब आप से कह रहा हूं—कि होम साइट्स जो आप ने दिये हैं उन से, जैसे कि गाव के बाहर एक जमाने मे आउट कास्ट्स होते थे, नये आउट-कास्ट्स तैयार कर रहे हैं। जो गरीब आदमी है उन को आप ने रेतीली जमीन, गड्ढों वाली जमीन दे दी और कह दिया कि इस पर अपने मकान बनाओ। इसलिए मेरा कहना यह है कि प्राग्राम इम्पलीमेंट वही कर पायेगे जो खुद उस मे इन्ट्रेस्टेड हों और उनकी कमेटीज बननी चाहिए।

अब लीगल एड कमेटी की बात आप लीजिए। आप ने इनडेटेडनेस को अबोलिश तो कर दिया लेकिन उस के लिए कोई आल्टरनेट मिकेनिज्म नही है। वह जाएगा कहा। साहूकार ने उसके गहने और बरतन वगैरह हड़प कर लिए है यह कह कर कि हमारे पास तुम्हारा कुछ नही है। वह बेचारा क्या करेगा। कई जगह साहूकार खुद मालगुजार भी होता है, जमीन वाला भी होता है। उसी के यहा उनको काम करना पड़ता है। वह कहा जाएगा। आल्टरनेटिव जब तक आप तैयार नही करते है तब तक वह जाएगा कहा। यह कहा मैने कि लीगल एड कमेटीज बननी चाहिये, गावो मे ही पीपल्स कमेटी बनानी चाहिये, पीपल्स कोर्टस वही की वही बने और वहा पर उनको न्याय मिलना चाहिये in terms of criminal and civil rights regarding these subjects. अगर यह चीज हो तो यह प्रेक्टिकल बात होगी। इसको आपको वहा एट दी ग्रास रूट लेवल करना चाहिये।

पैरिटी का सवाल भी आता है। इस साल बहुत अच्छी फसल हुई है। मैं समझता हू कि सारा झगड़ा देश में मार्किटिंग का है। किसान बुनियादी चीज पैदा करता है। अगर वह ज्यादा पैदा हो गई तो दाम गिर जाते हैं जबकि जो इनपुट्स हैं उस पर उसका कोई कट्रोल नही होता है और उसके दाम बढ़ते जाते है। एसेंशियल गुड्ज की मार्किटिंग को आपको कट्रोल करना पड़ेगा। ड्यूल मेकेनिज्म नही रहना चाहिये।

There must be only one national marketing agency for essential commodities दो आप काम करें। एक पोलिटिकल पार्टी का केडर फार इम्प्लेमेंटेशन आप तैयार करें और दूसरे नेशनल मार्किटिंग आर्गेनाइजेशन फार एसेंशियल कमोडिटीज हो। इसका दो तरफा फायदा होगा। पैरिटी के रूप मे दाम निर्धारित होंगे। किसान जो पैदा करता है उसके दाम भी आप फेयर दोगे साथ ही साथ कज्यूमर को भी ज्यादा दाम नही देने पडेगे। इससे होगा यह कि होलसेलर को एक दो परसेंट मिलेगा और चार पाच परसेंट रिटलर को मिलेगा और फिर यदि आपने व्हीट के दाम 105 के बजाय 110 भी दे दिए तो देश के किसी भी कोने मे कज्यूमर एड पर 130 या 140 से ज्यादा गेहू नही बिकेगा।

MR. SPEAKER: Just a minute. The time allotted for this Resolution is 2 hours. We have practically consumed the time. What is the consensus of the House?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI K. RAGHU RAMAIAH): Sir, this is an important Resolution. There is a long list of hon. Members who want to speak. I am sure, some others would also like to take part in the discussion. I am absolutely certain that it is the consensus of the House that the time should be extended by one hour.

SOME HON. MEMBERS: Two hours.

श्री रामावतार शास्त्री : (पटना) : श्री इन्द्रजीत गुप्त के प्रस्ताव का क्या होगा? वह आ जाना चाहिये ।

MR. SPEAKER: I cannot help it if the time on this Resolution is extended. It will be better if you move a motion for an extension of time.

SHRI K. RAGHU RAMAIAH: I move:

"That the time allotted for this Resolution be extended by another two hours"

MR SPEAKER: The question is:

"That the time allotted for this Resolution be extended by another two hours"

The motion was adopted.

MR SPEAKER: So, the time is extended by another two hours Shri Vasant Sathe to continue his speech

SHRI VASANT SATHE: As I was saying, there should be only one national marketing agency There must not be a dual system in the country Only then the parity of price will be possible It is only then that justice can be done to the producer of essential agricultural commodities as well as the consumer.

यदि आप ने मार्केटिंग अपने हाथ में ले लिया और उसमें होलसेलर्स और रिटेलर्स को शामिल कर लिया तो मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन एक मार्केटिंग आर्गेनाइजेशन बननी चाहिये । यदि आपने गाव मे पौल्टरी, पिग्गरी, हडीक्राफ्टस और एग्रो-इडस्ट्रीज स्थापित की और गाव के लोगों ने सामान पैदा किया तो उस सामान को खरीदेगा कौन ?

बडे इडस्ट्रीयलिस्ट स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज को कभी जिन्दा नही रहने देते । स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज तभी पनप सकती हैं, जब सरकार एक नेशनल मार्केटिंग एजेन्सी बनाये और यह तय करे कि वे लोग पैदा करे और हम मार्केटिंग करेंगे । तब सरकार उन लोगों को प्रोडक्टिव एम्पलायमेंट दे सकेगी । उसके बिना देहात का जीवन सुधर नही सकता है ।

लैंडलैस लेबरर्स को काम नही मिलता है, उनका जीवन तभी सुधर सकता है जब वे गुड्स प्रोड्यूस करे और उन चीजों को बेचने की उचित व्यवस्था हो । उन लोगों को प्रोडक्टिव वर्क दिया जाये । यह सब काम करने के लिए एग्रीकल्चरल रा-मैटीरियल बहुत है, उससे पेपर बन सकता है । मेरा ख्याल है कि हमें गाधी जी का भी कुछ ख्याल रखना चाहिये । हम उनको भूल रहे है । उनकी बेसिक फिलासफी यह थी कि—

"Agricultural products must be produced in a maximum decentralised way—cloth, paper, etc Why should we have Rs 1 crore plant for paper production? Why can't we have small plants dispersed to produce paper? Some such thinking can be done"

कल प्राइम मिनिस्टर ने चमडे के उद्योग के बारे में भाषण दिया । उन्होंने बडे सुन्दर ढग से कहा कि लोगों को इस काम को नीचा नही समझना चाहिये, डिग्निटी आफ लेबर होनी चाहिये । चमडे का उद्योग गाव का एक बडा उद्योग है । आज वह उद्योग कहा है ? बाटा और फेक्स ने गाव का यह सारा उद्योग खत्म करवा दिया है ।

17.47 hrs.

[SHRI BHAGWAT JHA AZAD *in the Chair*]

आज स्थिति यह है कि गाव मे एक उद्योग को भी नही रहने दिया जा रहा है । आवश्यकता इस बात की है कि हम गांव के

उद्योगों को बढ़ायें और उनमें सुधार करें । यदि आवश्यकता हो तो उन उद्योगों को माडर्नाइज़ किया जा सकता है । बिजली के साथ जहां मशीन, मोटर और पम्प वगैरह आ जायेंगे । गांव के लोग आधुनिक यंत्रों को अडाप्ट करने में किसी से पीछे नहीं हैं । उदाहरण के लिये उन्होंने ट्रेक्टर को अपना लिया है । हमारी यह धारणा गलत है कि गांव के लोग बुद्धिमान नहीं होते हैं, केवल इसीलिये कि वे अनपढ़ हैं ।

20 प्वाइन्ट प्रोग्राम एक कम्प्रीहैंसिव प्रोग्राम है । सारे गांव का जीवन उंचा उठाने के लिये इकानामिक योजनाओं को हाथ में लेना चाहिये । एक फैमिली के इकनामिक उत्थान के साथ अगर फैमिली प्लानिंग को जोड़ा जायेगा, तभी वह कामयाब होगा । वरना खाली फैमिली प्लानिंग की बात करने और निरोध का प्रचार करने से कुछ नहीं होगा । हमें लोएस्ट फैमिली का इकनामिक प्रोग्राम करना है ।

मैं दो बातों को फिर से दोहराना चाहता हूं । एक तो पोलिटिकल कैडर को रैस्पोंसेबिलिटी पावर और एकाउन्टेबिलिटी के साथ काम में लाया जाये । दूसरे एक नेशनल मार्केटिंग आर्गेनाइजेशन बनाई जाये जिसमें होलसेल और रिटेल ट्रेडर्स हों । उनको अलग न छोड़ा जाये वर्ना वे ब्लैक मार्केटिंग से मार देंगे । यदि सारे प्रोडक्टिव वर्क को डिसेंट्रलाइज कर देश भर में फैला दिया जाये तो देश का नक्शा बदल जायेगा और वह कार्यक्रम सफल होगा । प्लानिंग का उद्देश्य सफल होगा और फिर हम लोगों के पास जाकर कह सकेंगे कि हमने 20 सूत्री कार्यक्रम को सही ढंग से अमल में लाया है ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय, मैं ने आप से एक सवाल उठाने की इजाजत मांगी है । वह सवाल प्रधान मंत्री द्वारा घोषित 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम से सम्बन्धित है । मैं इस समय बुनकरों का सवाल उठाना चाहता हूं । हमारे देश में बुनकर लाखों की संख्या में हैं । स्वयं हमारे सूबे में भी उन की तादाद कुछ कम नहीं है ।

हमारे सूबे के कई ज़िलों में उन का सवाल है । जिस ज़िले से आप आते हैं, वहां--भागलपुर में--कल और परसों बुनकरों के सवाल को ले कर एक सूबाई कांफ्रेंस होने जा रही है । वहां से मुझे एक तार मिला है, जिस से यह ज्ञात होता है स्टपल सूत का दाम साठ प्रतिशत बढ गया है, जिस की वजह से भागलपुर में बुनकरों के बीच कुहराम मचा हुआ है । हजारों लोग बेकार हो रहे हैं और उन के करघे बन्द हो गये हैं ।

यह समस्या केवल भागलपुर तक ही महदूद नहीं है, बल्कि जहां जहां भी बुनकर हैं, करघे चलते हैं और कपड़ा बनता है, ऐसी तमाम जगहों में यह समस्या मौजूद है ।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जो प्रोग्राम जनता के सामने रखा गया है, उस की क्रियान्विति के सिलसिले में, और खास तौर से बुनकरों की समस्याओं का समाधान निकालने के सिलसिले में, कौन सी ठोस कार्रवाही उन्होंने की है । उन लोगों को सूत आसानी से और सस्ते दामों पर मिलना चाहिए । उन का कपड़ा नहीं बिकता है । क्यों नहीं सरकार उस कपड़े को ख़रीदने का इन्तज़ाम करती है ? जब तक सरकार इस तरह से बुनकरों की मदद नहीं करेगी--उन का कपड़ा ख़रीद कर, उन को सस्ता सूत दे कर और उन की दूसरी कठिनाइयों का हल निकाल कर, तब तक इस कार्यक्रम का यह सूत्र कार्यान्वित नहीं हो सकेगा और वह केवल काग़ज़ पर रह जायेगा ।

जहां तक मेरा अनुमान है, यह कार्यक्रम अभी तक काग़ज़ पर ही है । मैं इस कार्यक्रम

[श्री रामावतार शास्त्री]

का समर्थन जरूर करता हू, क्योंकि मेरी समझ मे इस कार्यक्रम की क्रियान्विति से गरीबों को बहुत दूर तक मदद मिलेगी । खास तौर से इस के छ या सात सूत्र देहातो से सम्बन्धित हैं और सामन्तवाद पर चोट करने वाले है । कुछ सूत्र मजदूरो और छात्रो से सम्बन्धित है । अगर सचमुच उन को क्रियान्वित किया जाये, तो आम जनता को पूरा लाभ होगा, और इसी कारण हमारा दल इस कार्यक्रम का समर्थन करता है ।

जहा खामी, कमी या कमजोरी है, उस के खिलाफ हम सघर्ष भी करते है, और कर रहे है—किसानो और मजदूरो के सघर्ष । कठिनाइया भी है । पुलिस के जुल्म और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम सघर्ष करते हैं ।

बुनकरो का सवाल अखिल-भारतीय सवाल है । कोई भी सूबा ऐसा नही है, जहा यह सवाल उपस्थित न हो । यह एक सीमित मसला नही है, बल्कि यह सम्पूर्ण देश का मसला है । इसलिए प्रधान मत्री ने बुद्धिमत्ता दिखाई है और इस सूत्र को भी इस कार्यक्रम मे जोडा है ।

इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए राज्यो और जिलो मे जो कमेटिया बन रही है, उन मे सौ सौ सदस्य रखे गये है । ऐसी भारी-भरकम कमेटियो से कुछ होने वाला नही है । वे लोग उन की बैठको मे नही जा पाते है, जो यह समझते है कि उन से कुछ काम नही होने वाला है । मैं भी यही समझता हू ।

आवश्यकता इस बात की है कि छोटी कमेटी बनाई जाये, और उन तमाम लोगो को उस मे रखा जाये, जो इस कार्यक्रम मे विश्वास रखते है । लेकिन इस समय क्या होता है ? जिले मे कमेटी बनी । कम्युनिस्ट पार्टी के एक प्रतिनिधि को उस मे रख लिया और बाकी अपने दल के लोगो को भर लिया । उस की मीटिंग भी नही होती है । अक्तूबर में पटना कार्यान्वियन समिति की आठ उपसमितियां बनीं । एक उप-समिति भूमि सुधार के लिए बनी हुई है । मुझे भी उस का मेम्बर बनाया गया है । लेकिन अक्तूबर के बाद आज तक उस की मीटिंग नही हुई । शायद यही स्थिति अन्य उप-समितियो की भी होगी । अभी हाल मे जिला कार्य समिति एक बनी है । उस की मीटिंग हुई है और आप को सुन कर ताज्जुब होगा कि बहुत सारे पार्लियामेंट के मेम्बरो को उस मे नही रखा गया । मुझे नही रखा गया । पता नही योजना कैसे क्रियान्विति होगी । पार्लियामेंट के मेम्बरों को मत रखो, असेम्बली के मेम्बरो को मत रखो, मुख्य मंत्री उसी को रखें जो उन की हा मे हा मिलाए, यह स्थिति रहेगी तो जाहिर बात है कि वह समिति काम नही कर सकेगी, अफसरो पर अकुश नही डाल सकेगी । उन कमेटियो को अधिकार दीजिए ताकि डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट, बी डी ओ, एस डी ओ मनमानी नही कर सके, जमीन निकल सके और जो जमीन मालिक किसानो पर जुल्म करे उन के खिलाफ तुरत कार्यवाही की जा सके । भूमि सुधार कानूनों मे आप परिवर्तन कीजिए ताकि लूपहोल्स नही रहे जिन का सहारा लेकर भूमिपति चले जाए हाई कोर्ट मे, सप्रीम कोर्ट मे और वर्षों लग जाय । इसलिए मैं चाहूंगा कि कार्यान्वयन समितिया छोटी छोटी बने, कारगर बने और उन मे सभी दलो के लोग रहे । तमाम जनता के प्रतिनिधियों का आप सहयोग लीजिए, जनता का सहयोग लीजिए तभी यह 20 सूत्री कार्यक्रम अमल मे आ सकेगा । मैं उम्मीद करूगा कि मत्री जी मेरे इन तमाम सवालो का जवाब देने की कोशिश करेंगे ।

श्री नरसिंह नारायण पांडे (गोरखपुर) सभापति जी, प्रधान मत्री ने जो 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम इस देश के सामने रखा है वह ऐसी परिस्थिति मे रखा है जिस परिस्थिति मे देश के अदर ऐसी प्रतिक्रियावादी पजीपरस्त ताकते देश और समाज को

कमजोर कर रही थी और बहुत दिनों से पार्टी के सामने, सरकार के सामने, लोक सभा मे और लोक सभा के बाहर

सभापति महोदय : मै समझता हू आप अभी और समय ले। अब आप अगले दिन जारी रखेंगे ।

The House now stands adjourned till 11 A.M. on Monday, the 19th January, 1976.

18 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, January 19, 1976/*Pausa* 29, 1897 (*Saka*).

GMGIPND—Job I—2035 LS—7C 2214—13-2.76—978